

प्रार्थना पत्र 14(4)

मु० न० 62/2021

उन्वान

तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम रामोतार पत्र 4

रेफरेंस अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ  
आवंटन नियम 1970 के नियम  
14(4)

उपस्थित :- श्री होगियार सिंह खड्कर - वकील  
अप्राचीण

निर्णय

दिनांक 24-7-2023

तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया है कि ग्राम अजीतगढ में भूमि ख० न० 1872 रकबा 0.44 हे० किल्लम कारानी 3 वर्तमान जमाबंदी के अनुसार राजस्व रिमांड में रामोतार पुत्र मुरलीधर, बशीधर पुत्र उभुदणाल के नाम से गैर खालेदारी अंकित है नियमन / आवंटन जरिये ख० न० 1872 रकबा 0.44 हे० में से रामोतार बशीधर निवासी अजीतगढ के नाम से रकबा 0.44 हे० का आवंटन दिनांक 18/02/2001 को होकर गैर खालेदारी दर्ज डूची थी

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कि धारा 16 में वर्णित है जिस पर आवंटन नियमन से खालेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। आवंटनी द्वारा आवंटन शर्तों कि पालना नहीं कि गई है। आवंटित भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 4 (V) (च) के अन्तर्गत आवंटन योग्य नहीं होने से आवंटन खालीज योग्य है। अतः आवंटन खालीज किया जाये।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं जारीये नोटिस अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण जारीये वकील उपस्थित एवं जारीये वकील जवाब पेश कर जवाब के विशेष कथन में उल्लिखित किया कि प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को हेरान व परेशान करने कि जर्ज से पेश किया गया है। भूमि के पुराने खण्ड नं० 1872 रकबा 0.44 है राजस्थान ग्राम सजीतगढ़ में स्थित है। उक्त भूमि का स्वामित्व प्रथम सैटलमेन्ट के समय राज्य सरकार के नाम से दर्ज होकर किल्म द्वारा राजस्थान कमिन्स में दर्ज हुई। उत्तरदाता भूमिहीन रहे है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थीगण का आवंटन आवेदन सर्वसमिति से स्वीकार किया गया। दिनांक 18-10-2001 को भूमि खण्ड नं० 1872 रकबा 0.44 है द्वारा तत्कालीन पटवारी हल्का कि सिफारिश रिपोर्ट के आधार पर आवंटित किये जाने का सर्वसमिति से निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय मात्र ही प्रभावी है। आवंटन नियम 13 A की पालना में उम्मा है। उक्त भूमि आवंटित होने के पश्चात समस्त व उपजाऊ खेप की मेहनत व खर्चे से करामी जाकर फसल पैदावार कर अपनी जीविकोपार्जन किया जाता रहा है। उक्त भूमि के पुराने खण्ड नं० 994 रकबा 2 बीघा 4 बिल्वा राजस्थान कमिन्स में दर्ज है। आवंटन आदेश दिनांक 18-10-2001 की पालना में नामान्तरण सं 983 दिनांक 5-4-2008 द्वारा जैर खालेदारी में दर्ज होकर बशीधर व रामोतार के नाम



Handwritten signature and official stamp of the Revenue Officer, Jaipur.

रिपोर्ट में अंकन हुआ। गैर जवाबदारी से जवाबदारी अधिकार दिये जाने हेतु कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 18 (1) में स्पष्ट किया है। तद्विपर स्वीकृति से आवंटन विधि से तीन वर्ष पश्चात आवंटन को जवाबदारी अधिकार प्रदान किया जावे। उक्त भूमि से गैर जवाबदारी व जवाबदारी अधिकारों से वंचित करने कि नियत से शिमायत व रिपोर्ट कर्मागो द्वारा भिन्ना इन्सुवेज बैचर किये गये। उक्त भूमि के तारबंदी कि हुई है। आवंटन प्रमाण बना रहे है। अतः प्रकरण में आपत्ति पेश कर निवेदन है कि प्रस्तुत प्रार्थना पर जवाबदारी किया जावे।

उभय पक्ष को सुना गया। पञ्जवली व पञ्जवली में उपलब्ध राजस्व रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पञ्जवली में उपलब्ध आवंटन मादेश कि फोटो प्रति के अवलोकन से पाया गया कि कृषीगण के पक्ष में भूमि खण्ड नं० 1872 बिस्म बा० कोष में से भूमि आवंटन हुई है। उक्त वस्तु भूमि कि बिस्म बाराही कोष ही। परवारी हल्मा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कृषीगण का दखल जो दिनांक 29.10.20 को पेश कि गई है। जिसमें कुं सं० 1 से 7 बिन्डुओं के सम्बन्ध में रिपोर्ट करनी चाहिए थी परन्तु समस्त बिन्डुओं का वस्तु रिपोर्ट नहीं कि गई है। जिससे प्रस्तुत रिपोर्ट अधूरी है। पञ्जवली में उपलब्ध नामान्वयित कि प्रति के अवलोकन से पाया गया कि कृषीगण के नाम से गैर जवाबदारी दर्ज कर दिनांक 5-4-2008 का नामांक स्वीकृत किया गया है। परवारी हल्मा द्वारा रिपोर्ट की गई है जिससे यह स्पष्ट होता है कि कृषीगण के नाम भूमि आवंटन हुई है तथा भूमि पर कृषीगण का कब्जा काश्त है। प्रार्थी द्वारा उक्त आवंटन स्वारीज योग्य बनाया है परन्तु इसमें कहीं भी स्पष्ट खुलासा नहीं किया गया है कि बिन्डु पर आवंटन स्वारीज योग्य है। उक्त भूमि कि बिस्म आवंटन के सम्बन्ध पर भी

बाराही कोष रिपोर्ट में दर्ज थी जिस बाबत भी कहीं अंकन नहीं किया है कि भूमि कि कितना बाराही कोष आवंटन योग्य है या नहीं। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई इल्हावेज पेश नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि मजिस्ट्रेट द्वारा आवंटन कि शर्तों कि पालना नहीं कि है। पत्रवारी दस्ता द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में आवंटन शुदा भूमि पर आवंटनीय का कलजा काश्त होना बताया है एवं पत्रवारी दस्ता द्वारा जो रिपोर्ट पेश कि गई है जिसमें भी सभी बिन्दुओं के बाबत स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है जिससे स्पष्ट पद स्थिति प्रतीत होती है। पत्रवारी दस्ता द्वारा अपनी ममिशंका रिपोर्ट जो दिनांक 29-10-2020 को पेश कि गई है जिसमें बिन्दु सं 3 के बाबत कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इन सभी बिन्दुओं एवं मौका स्थिति का स्पष्ट उल्लेख प्रार्थी द्वारा किया गया हो ऐसा कोई इल्हावेज पेशवली पर उपलब्ध नहीं है। पत्रवारी दस्ता द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भी अधूरी है। इसके पद प्रतीत होता है कि तख्तियाद श्रीमधोपुर द्वारा जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिससे सम्बंधित लम्बत राज्य रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन नहीं किया गया है जो किया जाना उचित है। प्रार्थी द्वारा मौके पर आवंटनी का कलजा है या नहीं इस बाबत भी कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। मजिस्ट्रेट को उम्ह भूमि दिनांक 18-10-2001 को आवंटन हुई थी। प्रार्थी द्वारा आवंटन निरस्त कराने हेतु जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) के तहत पेश किया गया है जो लगभग 22 वर्ष पश्चात पेश किया गया एवं जो भी सभी बिन्दुओं की गहनता से जांच किपे बिना पेश किया गया है। ....5....

(10/11/2020)  
 जिला मजिस्ट्रेट  
 बाराही

इस आधार पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मन्वगति धारा 14(4) का त्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मन्वगति धारा 14(4) का लाबित नहीं होने से त्वरीज किया जाता है। तथा तहसीलदार - श्रीमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र से सम्बंधित राजस्व रिमांड का गहनता से अवलोकन कर एवं इसके कि स्पष्ट जांच कर उन नियमानुसार कार्यवाही करें।

उक्त आदेश आज दिनांक 24-7-2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
 (अनिल कुमार)  
 अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
 एवं ज.सि. जिला नर्मल  
 नर्मल जिला